जनसत्ता

मर्यादा का उल्लंघन

जैसे-जैसे चुनाव का माहौल गरमा रहा है, नेताओं की वाणी से निकलने वाले शब्द कई बार विवाद का कारण भी बन जा रहे हैं। इससे माहौल भी खराब होता है और आचार संहिता का उल्लंघन भी। लेकिन समस्या तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल जैसा व्यक्ति या नीति आयोग के प्रमुख जैसा कोई वरिष्ठ नौकरशाह या अर्थशास्त्री ऐसी बातें करने लगे या टिप्पणी करे, जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती हो। हाल में ऐसे दो मामले आए। पहला मामला राजस्थान के राज्यपाल का और दूसरा नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। दोनों ही मामले तूल पकड़ गए। राजनीतिक दल सक्रिय हुए और चुनाव आयोग से कार्रवाई की गुहार लगाई। चुनाव आयोग ने दोनों ही मामलों को गंभीर मानते हुए चेतावनी दी। ऐसे में जो पहला सवाल उठा वह था पद की मर्यादा का। इन दोनों ही मामलों से ऐसा लगा कि पद की गरिमा और मर्यादा बाद में है, उससे पहले कहीं न कहीं किसी के प्रति निष्ठा दिखाना ज्यादा जरूरी है।

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने पिछले महीने की 23 तारीख को अलीगढ़ में मीडिया के सामने यह कह दिया था कि 'हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस नाते हमें भाजपा को जिताना है। हम सब चाहेंगे एक बार फिर से केंद्र में मोदीजी प्रधानमंत्री बनें...।' कल्याण सिंह राज्यपाल के पद पर नहीं होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन लगता है वे भूल गए कि वे अब राज्यपाल हैं, यह संवैधानिक पद है। ऐसे में उनकी निष्ठा अपनी या किसी अन्य पार्टी के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। कल्याण सिंह जो कुछ बोले, उससे यही संदेश गया कि वे चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए खुल कर काम कर रहे हैं। जब मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो आयोग ने इसे गंभीर माना और राष्ट्रपति से उनकी शिकायत की। राष्ट्रपति ने इसे विचार के लिए गृह मंत्रालय को भेजा है। देखने की बात यह है कि क्या ऐसा कोई फैसला आता है जो भविष्य के लिए नजीर बन सके। इससे पहले भी 1993 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद भी इसी तरह के विवाद में आ गए थे। वे भी अपने बेटे सईद अहमद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे। तब भी ऐसा ही विवाद मचा था और चुनाव आयोग ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया था और गुलशेर अहमद की राज्यपाली चली गई थी।

इसी तरह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी संयम नहीं बरता और कांग्रेस की प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) की आलोचना करते हुए कह दिया कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए चांद दिलाने का वादा कर रही है और वित्तीय व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली है। जब यह मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो आयोग ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया और सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देने में सतर्कता बरतने की चेतावनी दी। इस तरह की टीका-टिप्पणियां या बयान ऐसे महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों के विवेक पर सवाल खड़े करते हैं और साथ ही उन संस्थाओं की गरिमाओं को भी ठेस पहुंचती है जिसके वे मुखिया होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को क्या इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वे जो कह रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके इस बयान से क्या एक पार्टी विशेष के प्रति उनका झुकाव परिलक्षित नहीं होता! जब उच्च पदों, खासतौर से संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभाव ही स्थापित परंपराओं, मानदंडों और मर्यादा का खयाल नहीं रखेंगे तो समाज और राजनीति में क्या संदेश जाएगा!

हताश आतंकी

कश्मीर में दहशतगर्दों की हताशा इस कदर बढ़ती गई है कि अब वे उन्हीं लोगों की हत्या करने लगे हैं, जिनके लिए तथाकथित तौर पर संघर्ष का दावा करते हैं। इसका ताजा उदाहरण बारामूला के सोपोर में छुट्टी मनाने आए एक सैनिक के घर में घुस कर उसकी हत्या कर देने की घटना है। शनिवार रात को सैनिक के घर में घुस कर कुछ आतंकियों ने गोलीबारी की और उसे बहुत नजदीक से गोली मार दी। पिछले कुछ महीनों से आतंकियों ने घाटी में कश्मीरी मूल के सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाना शुरू किया है। पिछले साल उन्होंने त्राल इलाके में पर्चे चिपका कर अपील की थी कि कश्मीरी युवक पुलिस और सेना में न जाएं। स्थानीय लोगों से भी अपील की थी कि वे अपने बच्चों को सुरक्षा बलों में भर्ती होने से रोकें, नहीं तो कड़े कदम के लिए तैयार रहें। पर उनकी अपील का असर नहीं हुआ। कश्मीरी युवकों के सामने बड़ी समस्या रोजगार की है, सो वे दहशतगर्दों की अपीलों को अनसुना करते रहे। दहशतगर्दों ने इसे अपनी नाफरमानी माना और ऐसे युवाओं के खिलाफ हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। पिछली ईद के समय उन्होंने ऐसे तीन कश्मीरी युवाओं की हत्या कर दी, जो छुट्टी मनाने घर आ रहे थे या आए थे। फिर कश्मीर पुलिस में भर्ती हुए कुछ युवाओं को भी इसी तरह मार डाला।

दरअसल, जबसे सुरक्षाबलों ने घाटी में सघन तलाशी अभियान चलाया है और दहशतगर्दों के ठिकानों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की है, तब से उनका मनोबल काफी गिरा है। थोड़े-थोड़े अंतराल पर हिज्बुल के कई कमांडर मार गिराए गए। कश्मीरी युवाओं को हाथ में बंदूक उठाने के लिए उकसाने की उनकी कोशिशें कमजोर हुई हैं। पहले वे जिस तरह आम युवाओं को उकसा कर सेना पर पत्थरबाजी के लिए सड़कों पर उतारने में सफल हो जाते थे, वह भी अब बंद है। उधर, आम कश्मीरी नागरिकों ने उनकी सुरक्षाबलों का साथ देने की अपील ठुकरा दी। इससे उनकी हताशा और बढ़ी है। दहशतगर्दों को तभी ताकत मिलती है, जब स्थानीय लोग उन्हें समर्थन देते हैं। पिछले कुछ महीने पहले तक जब भी सुरक्षाबल आतंकियों के खिलाफ शिकंजे कसने का प्रयास करते थे, स्थनीय लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर देते थे। इस तरह उन्हें जो समर्थन मिला करता था, वह अब नहीं दिखता। इसलिए भी झुंझलाहट में वे सेना में भर्ती हुए घाटी के युवाओं को निशाना बना रहे हैं।

आम कश्मीरी के सामने बड़ी समस्या रोजगार की है। उनके बच्चे पढ़-लिख कर कोई रोजगार, कोई नौकरी करेंगे, तभी उनके जीवन में बेहतरी की उम्मीद जगेगी। अगर दहशतगर्द उसी पर रोक लगाएंगे, तो भला वे कैसे उनका समर्थन करेंगे। यह अच्छा संकेत है कि स्थानीय लोग दहशतगर्द संगठनों के दबाव से मुक्त हो रहे हैं। पर इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी सकारात्मक पहल की जरूरत है। अगर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, तो कश्मीरी युवाओं के भटकने की संभावना काफी कम रह जाएगी। फिर आतंकवाद के पनपने की असल वजहों को समझना भी जरूरी है। देखना होगा कि कुछ महीने पहले जिस बारामूला को आतंकवाद मुक्त जिला घोषित किया गया था, वहां आतंकियों का मंसूबा इस कदर कैसे बढ़ा कि घर में घुस कर एक सैनिक को मार डाला।

कल्पमेधा

जातियां व्यक्तियों से बनती हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवल संस्थाओं द्वारा होता है।
- डिजराइली

उपभोक्ता बाजार की चुनौतियां

जयंतीलाल भंडारी

भारतीय उपभोक्ता बाजार के विस्तार में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग अपने उद्यम-कारोबार, अपनी सेवाओं और पेशेवर योग्यताओं से न केवल अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं, वरन अपनी क्रय शक्ति से उपभोक्ता बाजार को भी मजबूत बना रहे हैं। देश में मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रयशक्ति उपभोक्ता बाजार को नई गति दे रही है।

भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2008 में इस उपभोक्ता बाजार महज इकत्तीस लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले साल यानी 2018 में एक सौ दस लाख करोड़ का हो गया। माना जा रहा है कि 2028 तक यह तीन गुना बढ़ कर तीन सौ पैंतीस लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। एक वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट में भारत के उपभोक्ता बाजार की तस्वीर पेश करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2008 से यह हर साल तेरह फीसद की दर से बढ़ रहा है। उपभोक्ता बाजार की यह वृद्धि देश में बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग की वजह से हो रही है। उपभोक्ता बाजार में उत्पादों के साथ-साथ सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है।

देश के उपभोक्ता बाजार के बढ़ने का एक बड़ा कारण ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ना भी है। डेलॉय इंडिया और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2021 तक चौरासी अरब डॉलर का हो जाएगा। वर्ष 2017 में यह चौबीस अरब डॉलर का था। भारत में ई-कॉमर्स बाजार सालाना बत्तीस फीसद की दर से बढ़ रहा है। निसंदेह ई-कॉमर्स ने देश में खुदरा कारोबार में क्रांति ला दी है। देश में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या साठ करोड़ से भी अधिक होने के कारण देश में ई-कॉमर्स की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। भारत के विशालकाय उपभोक्ता बाजार की मांग पूरी करने के लिए देश-विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं। उपभोक्ता बाजार की अपनी शक्ति के कारण भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

देश की बढ़ती जनसंख्या और उपभोक्ता बाजार का सीधा संबंध है। इस समय भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में भारत की आबादी एक सौ चौंतीस करोड़ और चीन की आबादी एक सौ इकतालीस करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। दुनिया के अन्य सभी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ेगी। भारत की यह विशालकाय आबादी सबसे बड़े वैश्विक उपभोक्ता बाजार का आधार भी होगी।

भारत में जैसे-जैसे उद्योगीकरण, कारोबारी विकास और शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे-वैसे देश का उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक ओर गांवों से रोजगार की चाह में लोगों का प्रवाह तेजी से शहरों की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के कारण लोग शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। वैश्वीकरण के नए परिदृश्य में भारतीय शहर प्रतिभाओं के लिए खुशहाली के नए केंद्र बन गए हैं। प्रतिभाएं शहरों में इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि शहरों में विश्वस्तरीय रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लेसमेंट सेंटर बनता जा रहा है। स्थिति यह है कि भारत के कई शहरों से विकसित देशों के लिए आउटसोर्सिंग का प्रवाह तेज होता जा रहा है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवर सरलता से मिल जाते हैं और व्यावसायिक कार्यस्थल पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम दरों पर उपलब्ध हैं।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नए शहरों का तेजी से विकास भारत में उपभोक्ता बाजार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। विश्व आर्थिक मंच ने इसी साल 'वैश्विक शहरीकरण में भारतीय शहरों की छलांग' से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दुनिया के सात सौ अस्सी बड़े और मझोले शहरों की बदलती आर्थिक तस्वीर और आबादी की बदलती प्रवृत्ति को लेकर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2035 तक दुनिया के शहरीकरण में काफी बदलाव आएगा। तेजी से विकसित होते हुए नए शहरों की रफ्तार के मामले में शीर्ष के बीस में पहले सत्रह शहर भारत के होंगे। इन शहरों से भारत का उपभोक्ता बाजार व्यापक बनेगा।

भारतीय उपभोक्ता बाजार के विस्तार में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग अपने उद्यम-कारोबार, अपनी सेवाओं और पेशेवर योग्यताओं से न केवल अपनी कमाई

बढ़ा रहे हैं, वरन अपनी क्रय शक्ति से उपभोक्ता बाजार को भी मजबूत बना रहे हैं। देश में मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रयशक्ति उपभोक्ता बाजार को नई गति दे रही है। भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ी है। इसी ताकत के बल पर भारत ने 2008 की मंदी से सबसे पहले निजात पाई थी। वर्ष 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के बाद देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या और खरीद क्षमता ऊंचाई पर पहुंच गई है और चारों ओर भारतीय मध्यम वर्ग का स्वागत हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फार अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या तीस करोड़ से अधिक है। देश में उच्च मध्यम वर्ग के सत्रह करोड़ लोग छियालीस फीसद क्रेडिट कार्ड, उनचास फीसद कार, बावन फीसदी एसी और तिरपन फीसद कंप्यूटर के मालिक हैं। मध्यम वर्ग की ताकत से चमकते हुए भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के उद्यमी और कारोबारियों के कदम भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय जब भारत की विकास दर दुनिया में सर्वाधिक सात फीसद के स्तर पर है, उसमें मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है। शेयर बाजार की ऊंचाई में भी मध्यम वर्ग की भूमिका है।

ऐसे में जब देश का उपभोक्ता बाजार बढ़ रहा है, तब उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी से बचाने और उनके हितों के संरक्षण की चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी हैं। जो उपभोक्ता आज बाजार की आत्मा कहा जाता है वह कई बार बाजार में मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, कम नापतौल जैसे शोषण से पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं हैं। उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए नए नियामक भी सुनिश्चित किए जाने जरूरी हैं।

नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के तहत भविष्य में डाटा की वही अहमियत होगी जो आज तेल की है। चूंकि आने वाली दुनिया उपभोक्ताओं डाटा पर आधारित होगी, इसलिए उपभोक्ताओं के उपयुक्त संरक्षण तथा मोबाइल डाटा उपभोग मामले में सबसे पहले भारत को डाटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। जिस देश के पास जितना ज्यादा डाटा संरक्षण होगा, वह देश आर्थिक रूप से उतना मजबूत होगा। चूंकि आर्थिक संदर्भ में डाटा एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई नियम-कानून नहीं हैं। अतएव इससे संबंधित उपयुक्त नियम कानून जरूरी हैं। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि डाटा पर देश का ही नियंत्रण हो और खास डाटा को भारत में ही रखा जाए। डाटा के देश में ही भंडारण की आवश्यकता इसलिए है, ताकि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण हो सके और अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर उपभोक्ताओं का ही नियंत्रण रहे। ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर तमाम पाबंदी लगाई जानी जरूरी है। उपभोक्ता बाजार से जहां भारतीय उपभोक्ताओं की मांग पूरी होगी, कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी, तभी देश की विकास दर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।

आधा गिलास पानी

प्रयाग शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

जिन्हें जल-संकट का गहरा भान है, वे गहराई से जल के बचत की बात भी सोचने लगे हैं। मेरे एक मित्र प्यास के हिसाब से ही अपना गिलास भरते या भरवाते हैं। उनका कहना है कि हमें गरमी में भी हर वक्त तो प्यास लगी नहीं होती है! मान लीजिए कि घर से आप थोड़ी देर पहले ही पानी पीकर चले हैं और थोड़ी देर बाद किसी पड़ोसी के यहां पहुंचे हैं या पास में किसी से मिलने, तो आपसे पानी के लिए पूछा जाएगा या खुद वह आपके सामने कुछ पलों बाद रख दिया जाएगा। कई बार हम उस पानी के 'सम्मान' में प्यास न लगी होने के बावजूद उसे उठा लेते हैं और दो-चार घूंट भर कर बाकी छोड़ देते हैं। वह जूठा पानी फेंक दिया जाता है। अगर प्यास नहीं लगी है तो हम जरा 'जोर' से मना कर सकते हैं कि 'नहीं अभी तो प्यास ही नहीं है' या फिर अगर कुछ प्यास है तो कह सकते हैं- 'भाई, आधा गिलास ही दीजिएगा।'

मेरे मित्र यह भी बताते हैं कि आधा गिलास वाली बात सुन कर कुछ लोग चौंकते हैं, हंसने तक लगते हैं। लेकिन कुछ उनकी ओर प्रशंसा भाव के साथ देखते हैं। यह प्रशंसा के लायक है भी। न जाने कितना पानी, असावधानी के कारण या 'जाने-अनजाने' हम बर्बाद करते हैं। कई बार लोग नल के सामने जब मुंह धो रहे होते हैं, तो मुंह पर पानी के छींटे देते हुए नल को खुला ही रहने देते हैं और जब तक दूसरे छींटे के लिए हथेली जल भरने को फिर नीचे आती हैं, पानी बहता ही रहता है नल से। यह भी एक सामान्य-सी प्रवृत्ति है कि बहुत-से लोग होटल या गेस्ट हाउस के पानी को 'अपना' नहीं मानते और अगर वह बर्बाद हो रहा होता है, तो उसकी परवाह नहीं करते।

'आधा गिलास पानी' वाले हमारे मित्र, जल-संकट की चर्चा के समय यह आग्रह भी करते हैं कि पानी कहीं का हो, उसे 'अपना' मान कर चलना ही ठीक है। इससे भी होगी जल की बचत। वह नदी का हो, नहर-झील-सरोवर का हो, कहीं के नल, फव्वारे, पार्क, रास्ते का हो, वह 'अपना' है। इतना मानते ही हम कहीं किसी पाइप के फट जाने पर उससे बहते पानी को देख कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, किसी संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना देंगे। कहीं किसी ने नल खुला छोड़ दिया है, तो उसे बंद करने की बात सोचेंगे। क्या यह सच नहीं है कि अगर नदियों के जल को सभी ने अपना माना होता, तो वह जल इतना ज्यादा प्रदूषित न हुआ होता। हम अब भी जल-संकट को दैनिक सामाजिक आचार-व्यवहार में उतना गंभीर नहीं मान रहे हैं, जितना कि वह सचमुच हो चुका है। करोड़ों देशवासी जल-संकट से बुरी तरह जूझ रहे हैं गरमी में यह संकट और बढ जाता है।

यह संकट इतना गहरा है कि अब पर्व-त्योहारों पर भी पानी की बचत की बात सोचनी पड़ेगी। पर्व-त्योहारों पर, होली-दिवाली पर, पानी के मामले में भी, हमारे हाथ कुछ अधिक खुल जाते हैं। कुएं पहले जैसे रहे नहीं, सरोवरों पर भी संकट बना हुआ है। 'आधा गिलास पानी' वाली बात भी बहुतों को भले ही एक अतिरंजित कोशिश लगे, पर उसके प्रतीकार्थ को तो कोई भी कम करके नहीं आंकना चाहेगा। जब भी मैं गरमी में ऐसी तसवीरें अखबारों में देखता हूं, जिनमें स्त्रियां मीलों दूर से घड़ों में पानी लाती हुई दिखती हैं, या किसी बस्ती में स्त्री-पुरुष, किसी नल या टैंकर के सामने लंबी कतारों में नजर आते हैं, तो पीड़ा होती है। तब लगता है कि जल की एक-एक बूंद कितनी कीमती है।

हां, यह जरूर सुखद है कि इस बीच वर्षा जल संचय की विधि कई जगहों में अपनाई गई है। बस्तियों-मुहल्लों में जल-संशोधनों पर काम हुआ है। कहीं तालाब साफ किए गए हैं, कहीं नए बनाए गये हैं। ऐसे प्रयत्नों की और भी जरूरत है।

जब अपने बचपन की याद करता हूं, तो पाता हूं कि कुओं की कमी न थी। नदियां प्रदूषित न थी। अपनी आंखों से गंगा-यमुना के जल को निर्मल देखा है। और गांवों में ही नहीं, कोलकाता जैसे महानगर में कई सरोवरों का दिख जाना एक सहज दृश्य था। उनमें कुछ आज भी बचे हुए हैं। चिंता तब और अधिक होती है, जब उन प्रदेशों में, जहां काफी बारिश होती थी और आज भी होती ही है; वहां भी गरमी में जल-संकट ऊपर आ जाता है। फसलों को पानी चाहिए। खेतिहर मजदूरों को पानी चाहिए। लेकिन सचमुच 'बिन पानी सब सून' ही तो है। गरमी में ऐसे समचार भी कितना दुख देते हैं कि कई जगहों में पशुओं को चारा-पानी न दे पाने के कारण किसान उन्हें बेचने तक को मजबूर हो जाते हैं। जल के नए संसाधन, नये स्रोत ढूंढ़ना जितना जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत इस बात की है कि हम बचे हुए पानी को बचाए रखें, उसे बर्बाद न होने दें।

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चुनाव का मौसम

लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान और उसके बाद आदर्श आचार संहिता लगने के समय से ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई थीं। रैलियों का दौर शुरू होते ही बेपरवाह राजनीतिक बयानबाजी भी चरम सीमा पर पहुंच गई और जनता के आम मुद्दे और समस्याएं काफी पीछे छूट गए, लेकिन पहले चरण के मतदान के तकरीबन दस दिन पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर राजनीतिक माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में डुबो दिया। कांग्रेस ने सोची-समझी रणनीति के तहत अन्य दलों से पहले घोषणापत्र जारी कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इसका दूसरा पहलू यह भी था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव मैदान में हैं। वायनाड कांग्रेस की पारंपरिक सीट नहीं है और वाम दल भी वहां मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नामांकन से पहले अपने घोषणापत्र में लोकलुभावन वादे कर राहुल की प्रतिबद्धता और नए दृष्टिकोण को सामने रखने की भरपूर कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस ने भारी-भरकम वादों की घोषणा कर सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में खुद को पेश किया। हालांकि इन सबसे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को टक्कर देना उसका सीधा मकसद था।

● *शिवांशु राय, वाराणसी*

विरोधी देशद्रोही नहीं

भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी का कथन उचित है। विपक्ष में चाहे कोई भी दल हो, उसका काम सत्ताधारी दल से सवाल-जवाब करना होता है। इसका माकूल व तर्कपूर्ण जवाब देने का काम सत्ताधारियों का होता है, लेकिन सवालों से बचने के लिए किसी भी विरोधी को देशद्रोही कहना प्रजातंत्र का अपमान है। प्रजातंत्र की अवधारणा इसी पर रखी है कि पक्ष के साथ विपक्ष होना चाहिए, ताकि एकतंत्रीय निरंकुश शासन व्यवस्था न हो। इसलिए आडवाणी का बयान आज की गंदी राजनीति के लिए एक सबक है। जो नेता खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान का पक्ष लेकर बयानबाजी करते हैं, वे जरूर देशद्रोही हैं क्योंकि उनकी विचारधारा देश हित में नहीं है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन*

वेनेजुएला न बन जाए भारत

राहुल गांधी 72000 रुपए बांटने वाली अपनी योजना के लिए पैसा कहां से लाएंगे, यह अब कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगा है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि लोगों को कुछ अधिक टैक्स देने का मन बना लेना चाहिए। यहां यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि राहुल के पिता राजीव गांधी के समय दिल्ली से भेजे गए 100 रुपए में से केवल 15 रुपए अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। अब देखना होगा कि 72000 रुपए में से कितने पहुंच पाते हैं। वैसे यह योजना नाकारा लोगों की संख्या और बढ़ाएगी, इस तथ्य की ओर कांग्रेस का ध्यान ही नहीं गया। कोई व्यक्ति 12 हजार महीना कमा रहा है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ न कमाने वाले को सरकार अपनी ओर से 12000 दे देगी। जब खाली बैठकर ही 12000 रुपए मिल सकते हैं तो लोग काम करने की जहमत क्यों उठाएंगे? वेनेजुएला में आर्थिक संकट की जड़ में इसी तरह की नीतियां थीं। लोग धीरे-धीरे कुछ न करके सरकार के सहारे रहकर पेट भरने लगे। 1973 के बाद पेट्रोलियम की बढ़ती सरकारी कमाई से लोगों को निरंतर पैसा मिलता रहा। फिर जब कच्चे तेल के दाम गिरे तो वेनेजुएला भी घुटनों के बल गिरा। सो खून के आंसू रो रहे हैं। भारत को भी इस लॉलीपॉप से सावधान रहने की जरूरत है।

● *पूनम मित्तल, मेरठ*

संकट में गुरु-शिष्य रिश्ता

समय के साथ बच्चे बदल रहे हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा हाईटेक हो रही है, लेकिन समय के साथ कुछ अध्यापक बदल नहीं पा रहे हैं। वे बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनका मान-सम्मान करते रहें, लेकिन किसी न किसी स्तर पर आई खामियों की वजह से शिक्षक और विद्यार्थियों में आज वह संबंध नहीं रह गया है जो संबंध पूर्व के गुरु-शिष्य में हुआ करता था। जबकि होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह आज अधिक बच्चे पढ़-लिख रहे हैं, अधिक बच्चे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उसी तरह शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध में अधिक प्रगाढ़ता भी आनी चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और संक्रमित हो रही संस्कृति का दुष्परिणाम है कि दोनों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और यही कारण है कि विद्यालय स्तर पर भी कभी-कभी विद्यार्थी विद्रोह करते नजर आ जाते हैं। ऐसे में समाज और शिक्षकों को सोचना होगा कि वे कैसा भविष्य चाहते हैं। इसके लिए कुछ सार्थक प्रयास करने होंगे। अभिभावकों को भी सक्रिय होकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से सुसंस्कृत करने पर बल देने की जरूरत है।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*

मत का सही इस्तेमाल

मताधिकार एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसे मतदाता किसी भी बेईमान दल या प्रत्याशी के पांव पर मार सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों ने जोड़-तोड़ कर मतदाताओं को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि कुल्हाड़ी घूम-फिरकर उन्हीं के पैरों में जा लगती है। जब किसी भी दल का प्रत्याशी पसंद न हो तो मतदाता किसी को भी मत देने के लिए विवश हो जाता है। आजकल कहीं दल के कारण तो कहीं प्रत्याशी के कारण अधिकतर मतदाता इसी स्थिति में हैं। राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो जाने से मतदाताओं को कभी अच्छा प्रत्याशी तो कभी अच्छा दल छोड़ना पड़ता है। कई जगह तो स्थिति यह हो जाती है कि मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आता। ऐसे में उसके पास नोटा का बटन दबाने या वोट न डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इससे भी राजनीतिक दलों को ही फायदा होता है। इसीलिए मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर ही किया जाना चाहिए।

● *डॉ पुष्पलता, मुजफ्फरनगर*